पूर्व प्रधान मंत्री ने गैर-सरकारी दौरों के लिए 2 अप्रैल, 1991 अर्थात् राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्ग-निर्देशन के लिए जारी की गई आदर्श आचरण संहिता का पैरा 7 लागू होने की तारीख से 13 जून, 1991 अर्थात् चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की तारीख तक कुल 1307.10 घंटों की उड़ान की। पूर्व उप प्रधान मंत्री को इस अवधि के दौरान गैर-सरकारी दौरों के लिए कोई वायुयान उपलब्ध नहीं कराया गया।

पूर्व प्रधान मंत्री द्वारा गैर-सरकारी दौरों के लिए इस्तेमाल किए गए वायुयान के प्रभार के रूप में वायुसेना को कुल लगभग 412 लाख रुपए (चार सौ बारह लाख रु०) की अदायगी की जानी है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। वायुसेना मुख्यालय को खर्च के दावे तैयार करने से पूर्व जांच कार्य करने में कुछ समय लगता है। अप्रैल, 1991 को समाप्त अवधि के बिल तैयार कर लिए गए हैं।

1512. *[Transferred to the 10th Sep. 1991.]*

गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों की मासिक आय

1513. **श्री रणजीत सिंह :**
डा. जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1987-88 के दौरान 237.67 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे थे;

(ख) यदि हां, तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले इन लोगों की अधिकतम मासिक आय क्या है;

(ग) क्या मुद्रास्फीति की दर में हो रही वार्षिक वृद्धि को देखते हुए वर्तमान स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की मासिक आय का ऐसा आकलन सही है; और

(घ) यदि नहीं, तो मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि को देखते हुए यह राशि कितनी होनी चाहिए?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण घरेलू खपत व्यय संबंधी हंसराज आंकड़े एकत्रित करता है। योजना आयोग इन आंकड़ों का प्रयोग करते हुए तथा न्यूनतम आवश्यकताओं एवं प्रभावी खपत मांग पर कैलोरी बल द्वारा संस्तुत गरीबी-रेखा के आधार पर देश में गरीबों की संख्या एवं अनुपात का अनुमान लगाता है। वर्ष 1987-88 में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या 237.67 मि० होने का अनुमान है।

(ख) गरीब लोगों से अभिप्राय उन लोगों से है जिनका प्रति व्यक्ति अधिकतम मासिक खपत व्यय वर्ष 1987-88 में गरीबी रेखा से नीचे अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में 131.80 रु० तथा शहरी क्षेत्रों में 152.13 रु० था।

(ग) और (घ) कीमत स्तर में परिवर्तनों को देखते हुए गरीबी रेखा को अद्यतन बनाया जाता है।

आम चुनावों की घोषणा के बाद सरकारी पदों पर नियुक्तियां

1514. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछली सरकार ने आम चुनावों की घोषणा के बाद बड़ी संख्या में सरकारी पदों पर नियुक्तियां की थीं;

(ख) क्या यह भी सच है कि निर्वाचन आयोग ने भी ऐसी नियुक्तियां न करने के लिए कहा था;

(ग) यदि हां, तो ये नियुक्तियां कौन-कौन से विभागों में किन-किन पदों पर की गई थीं;

(घ) इन पदों पर नियुक्त अथवा नामांकित व्यक्तियों के नाम, उनकी शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव क्या-क्या हैं साथ ही ये नियुक्तियां किन-किन पदों पर की गई हैं;

(ङ) क्या सरकार इन नियुक्तियों को गैर न्यायोचित घोषित करके इन्हें रद्द करेगी; और

(च) यदि हां, तो अब तक कितनी नियुक्तियां रद्द की गई हैं तथा शेष नियुक्तियों को कब तक रद्द किये जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) जी, हां।

(ख) निर्वाचन आयोग ने केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में सभी पदों की नियुक्तियों पर रोक लगाने के कोई निर्देश जारी नहीं किए थे।

(ग) से (च) ये प्रश्न नहीं उठते।

Development Projects in the area of Computer and Sanskrit

1515. SHRI KRISHAN LAL SHARMA:
SHRIMATI SUSHMA SWARAJ::

Will the PRIME MINISTER be pleased to state::

(a) whether it is a fact that a number of development projects have been funded in the area of computer and Sanskrit by technical Departments;

(b) if so, what is the extent of funding from different departments;

(c) whether there is any mechanism of their coordination and monitoring; if so whether it is quarterly, half yearly or yearly; and whether they are different or the same;

(d) what is the mechanism to evaluate results of projects funded by the different Departments and to suggest integration of technologies, and to ensure effective interdepartmental coordination and monitoring of the projects; and

(e) how do sponsoring technical departments provide technical support in initial selection and installation of computing facilities, organising computer orientation programme at Sanskrit Institution?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) and (b) Yes, Sir. A number of development projects have been initiated in the area of computer and Sanskrit by the Department of Electronics and the Ministry of Science and Technology. The details of the projects are given in the statements-I and II.

(c) The projects are being monitored through periodic reports and by specific monitoring and coordination committee twice or thrice a year. The coordination of the projects funded by the Department of Electronics is done by the Department itself. The coordination of the projects funded by the Ministry of Science and Technology is done by the National Institute of Science and Technology Development Studies (NISTADS).

The monitoring committees for different projects are constituted on the basis of specialisation and expertise of the members in a particular area.

(d) The evaluation of the results of the projects are done by the monitoring and coordination committees. Interdepartmental coordination is achieved through the Project Advisory Committee of the Technology Development for Indian Languages (TDIL) involving specialists from various departments.

(e) The Department of Electronics who is sponsoring a major programme in this area namely, TDIL is providng technical support in computer and Sanskrit institutions by sponsoring training programmes and involving computer institutons for joint programmes.